>

Title: Need to provide separate data of Other Backward Classes in the caste-based census in the country.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): मैं नियम 377 के तहत सरकार से जनगणना 2011 में सदन में सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी अन्य पिछड़े वर्ग की गणना नहीं किए जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा आपसे पूछना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई की गई है और जाति आधारित जनगणना का चरण कहां तक पहुंची है। सरकार ने सदन को काफी समय पहले आश्वासन दिया था पर आज तक उस परिप्रेक्ष्य में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जब जनगणना हुई थी तब ही अगर एक कॉलम डाल दिया गया होता तो सरकार पर जनगणना का दोबारा व्यय नहीं पड़ता। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जाति आधारित जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना भी की जाए।